OVERVIEW

Let us shift our gaze from the larger global developments in the post-Cold War era to developments in our own region, South Asia. When India and Pakistan joined the club of nuclear powers, this region suddenly became the focus of global attention. The focus was, of course, on the various kinds of conflict in this region: there are pending border and water sharing disputes between the states of the region. Besides, there are conflicts arising out of insurgency, ethnic strife and resource sharing. This makes the region very turbulent. At the same time, many people in South Asia recognise the fact that this region can develop and prosper if the states of the region cooperate with each other. In this chapter, we try to understand the nature of conflict and cooperation among different countries of the region. Since much of this is rooted in or conditioned by the domestic politics of these countries, we first introduce the region and the domestic politics of some of the big countries in the region.

परिचय

आइए, अब हम शीत युद्ध के दौर में विश्व के एक बड़े प् nलक पर हुए बदलावों से नज़र हटा कर अपना ध्यान अपने क्षेत्र यानी दक्षिण एशिया की ओर मोड़ें। बीसवीं सदी के आख़िरी सालों में जब भारत और पाकिस्तान ने खुद को परमाणु शक्ति-संपन्न राष्ट्रों की बिरादरी में बैठा लिया तो यह क्षेत्र अचानक पूरे विश्व की नज़र में महत्त्वपूर्ण हो उठा। स्पष्ट ही विश्व का ध्यान इस इलाके में चल रहे कई तरह के संघषों पर गया। इस क्षेत्र के देशों के बीच सीमा और नदी जल के बँटवारे को लेकर विवाद कायम है। इसके अतिरिक्त विद्रोह, जातीय संघर्ष और संसाधनों के बँटवारे को लेकर होने वाले झगड़े भी हैं। इन वजहों से दक्षिण एशिया का इलाका बड़ा संवेदनशील है और अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि आज विश्व में यह क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका वाला क्षेत्र है। साथ ही एक बात और है। इस इलाके के बहुत से लोग इस तथ्य की निशानदेही करते हैं कि दक्षिण एशिया के देश अगर आपस में सहयोग करें तो यह क्षेत्र विकास करके समृद्ध बन सकता है। इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया के देशों के बीच मौजूद संघषों की प्रकृति और इन देशों के आपसी सहयोग को समझने की कोशिश करेंगे। दक्षिण एशिया के देशों की घरेलू राजनीति से इन झगड़ों या सहयोग का मिज़ाज तय होता है अथवा वह इनके मूल में हैं। इस वजह से अध्याय में पहले दक्षिण एशिया का परिचय दिया जाएगा और कुछ देशों की घरेलू राजनीति की चर्चा की जाएगी।



The various countries in South Asia do not have the same kind of political systems. Despite many problems and limitations, Sri Lanka and India have successfully operated a democratic system since their independence from the British. It is, of course, possible to point out many limitations of India's democracy; but we have to remember the fact that India has remained a democracy throughout its existence as an independent country. The same is true of Sri Lanka.

दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक-सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। अनेक समस्याओ और सीमाओं के बावजूद भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद, लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। भारत के लोकतंत्र की बहुत सारी सीमाओं की तरफ इंगित किया जा सकता है लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि एक राष्ट के रूप में भारत हमेशा लोकतांत्रिक रहा है। यही बात श्रीलंका पर लागू होती है।

Pakistan and Bangladesh have experienced both civilian and military rulers, with Bangladesh remaining a democracy in the post-Cold War period. Pakistan began the post-Cold War period with successive democratic governments under Benazir Bhutto and Nawaz Sharif respectively. But it suffered a military coup in 1999 and has been run by a military regime since then. Till 2006, Nepal was a constitutional monarchy with the danger of the king taking over executive powers. In 2006 a successful popular uprising led to the restoration of democracy and reduced the king to a nominal position. From the experience of Bangladesh and Nepal, we can say that democracy is becoming an accepted norm in the entire region

पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है। शीतयुद्ध के बाद के सालों में बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम रहा। पाकिस्तान में शीतयुद्ध के बाद के सालों में लगातार दो लोकतांत्रिक सरकारें बनीं। पहली सरकार बेनज़ीर भुट्टो और दूसरी नवाज शरीप क के नेतृत्व में कायम हुई। लेकिन इसके बाद 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट हुआ। तब से यहां सैनिक-शासन है। 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था और इस बात का खतरा बराबर बना हुआ था कि राजा अपने हाथ में कार्यपालिका की सारी शक्तियां ले लेगा। लेकिन, 2006 में एक सफल जन-विद्रोह हुआ और यहां लोकतंत्र की बहाली हुई। राजा की हैसियत न के बराबर रह गई। बांग्लादेश और नेपाल के अनुभवों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरे दक्षिण एशिया में लोकतंत्र एक स्वीकृत मूल्य बन चला है।

Similar changes are taking place in the two smallest countries of the region. Bhutan is still a monarchy but the king has initiated plans for its transition to multi-party democracy. The Maldives, the other island nation, was a Sultanate till 1968 when it was transformed into a republic with a presidential form of government. In June 2005, the parliament of the Maldives voted unanimously to introduce a multi-party system. The **Maldivian Democratic Party** (MDP) dominates the political affairs of the island. Democracy strengthened in the Maldives after the 2005 elections when some opposition parties were

दक्षिण एशिया के दो सबसे छोटे देशों में भी एसे ही बदलाव की बयार बह रही है। भूटान में अब भी राजतंत्र है लेकिन यहां के राजा ने भूटान में बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित करने की योजना की शुरुआत कर दी है। दूसरा द्वोपीय देश मालदीव 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। 1968 में यह एक गणतंत्र बना और यहां शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनायी गयी। 2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एकमत से मतदान किया। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) का देश के राजनीतिक मामलों में दबदबा है। 2005 के चुनावों के बाद मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ है क्योंकि इस चुनाव में विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता दे दी गई।

Despite the mixed record of the democratic experience, the people in all these countries share the aspiration for democracy. A recent survey of the attitudes of the people in the five big countries of the region showed that there is widespread support for democracy in all these countries. Ordinary citizens, rich as well as poor and belonging to different religions, view the idea of democracy positively and support the institutions of representative democracy. They prefer democracy over any other form of democracy and think that democracy is suitable for their country. These are significant findings, for it was earlier believed that democracy could flourish and find support only in prosperous countries of the world. In that sense the South Asian experience of democracy has expanded the global imagination of

दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकार्ड मिला-जुला रहा है। इसके बावजूद दक्षिण एशियाई देशों की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी है। इस क्षेत्र के पाँच बड़े देशों में हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण से यह बात जाहिर हुई कि इन पाँचों देशों में लोकतंत्र को व्यापक जन-समर्थन हासिल है। इन देशों में हर वर्ग और धर्म के आम नागरिक – लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। इन देशों के लोग शासन की किसी और प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र को वरीयता देते हैं और मानते हैं कि उनके देश के लिए लोकतंत्र ही ठीक है। ये निष्कर्ष बड़े महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि पहले से माना जाता रहा है कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में फल-फूल सकता है। इस लिहाज से देखें तो दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ा है।

Let us look at the each of the four big countries of the region other than India.

आइए, हम देखें कि भारत को छोड़कर experience of democracy in दक्षिण एशिया के अन्य चार बड़े देशों में लोकतंत्र का अनुभव कैसा रहा?

THE MILITARY AND DEMOCRACY IN PAKISTAN

After Pakistan framed its first constitution, General Ayub Khan took over the administration of the country and soon got himself elected. He had to give up office when there was popular dissatisfaction against his rule. This gave way to a military takeover once again under General Yahya Khan. During Yahya's military rule, Pakistan faced the Bangladesh crisis, and after a war with India in 1971, East Pakistan broke away to emerge as an independent country called Bangladesh. After this, an elected government under the leadership of Zulfikar Ali Bhutto came to power in Pakistan from 1971 to 1977 The Rhutto government was

पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र

पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद देश के शासन की बागडोर जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली और जल्दी ही अपना निर्वाचन भी करा लिया। उनके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का और एसे में उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। इससे एक बार फिर सैनिक शासन का रास्ता साफ हुआ और जनरल याहिया खान ने शासन की बागडोर संभाली। याहिया खान के सैनिक-शासन के दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश-संकट का सामना करना पड़ा और 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ। युद्ध के परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बना और बांग्लादेश कहलाया। इसके बाद पाकिस्तान में जुल्पि ककार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी जो 1971 से 1977 तक कायम रही। 1977 में जेनरल जियाउल-हक ने इस सरकार को गिरा दिया

General Zia faced a prodemocracy movement from 1982 onwards and and an elected democratic government was established once again in 1988 under the leadership of Benazir **Bhutto. In the period that** followed, Pakistani politics centred around the competition between her party, the Pakistan People's Party, and the Muslim League. This phase of elective democracy lasted till 1999 when the army stepped in again and **General Pervez Musharraf** removed Prime Minister Nawaz **Sharif. In 2001, General** Musharraf got himself elected as the President. Pakistan continued to be ruled by the army, though the army rulers have held some

1982 के बाद जेनरल जियाउल-हक को लोकतंत्र-समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा और 1988 में एक बार फिर बेनज़ीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी। पाकिस्तान में इसके बाद की राजनीति बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के आपसी होड के इर्द-गिर्द घूमती रही। निर्वाचित लोकतंत्र की यह अवस्था 1999 तक कायम रही। 1999 में एक बार फिर सेना ने दखल दी और जेनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीप क को हटा दिया। 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में कराया। पाकिस्तान पर सेना की हुकूमत थी हालाँकि सैनिक शासकों ने अपने शासन को लोकतांत्रिक जताने के लिए चुनाव कराए हैं।

Several factors have contributed to Pakistan's failure in building a stable democracy. The social dominance of the military, clergy, and landowning aristocracy has led to the frequent overthrow of elected governments and the establishment of military government. Pakistan's conflict with India has made the promilitary groups more powerful. These groups have often said that political parties and democracy in Pakistan are flawed, that Pakistan's security would be harmed by selfish-minded parties and chaotic democracy, and that the army's stay in power is, therefore, justified. While democracy has not been fully successful in Pakistan, there has been a strong pro-democracy sentiment in the country. Pakistan has a courageous and relatively free nroce and a etrona human riabte

पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के कई कारण हैं। यहां सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है। इसकी वजह से कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ। पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है। इस वज़ह से सेना-समर्थक समूह ज्यादा मजबूत हैं और अक्सर ये समूह दलील देते हैं कि पाकिस्तान के राजनीतिक दलों और लोकतंत्र में खोट है। राजनीतिक दलों के स्वार्थ साधन तथा लोकतंत्र की धमाचौकड़ी से पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। इस तरह ये ताकतें सैनिक शासन को जायज ठहराती हैं। लोकतंत्र तो खैर पाकिस्तान में पूरी तरह सफल नहीं हो सका है लेकिन इस देश में लोकतंत्र का जज्बा बहुत मज़बूती के साथ कायम रहा है। पाकिस्तान में अपेक्षाकृत स्वतंत्र और साहसी प्रेस मौजूद है और वहां मानवाधिकार आंदोलन भी काफी मजबूत है।

The lack of genuine international support for democratic rule in Pakistan has further encouraged the military to continue its dominance. The United States and other Western countries have encouraged the military's authoritarian rule in the past, for their own reasons. Given their fear of the threat of what they call 'global Islamic terrorism' and the apprehension that Pakistan's nuclear arsenal might fall into the hands of these terrorist groups, the military regime in Pakistan has been seen as the protector of Western interests

पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले- इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता। इस वज़ह से भी सेना को अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए बढ़ावा मिला है। अमरीका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने-अपने स्वाथों से गुज़रे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन का बढ़ावा दिया। इन देशों को उस आतंकवाद से डर लगता है जिसे ये देश 'विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद' कहते हैं। इन देशों को यह भी डर सताता है कि पाकिस्तान के परमाण्विक हथियार कहीं इन आतंकवादी समूहों के हाथ न लग जाएँ। इन बातों के मद्देनज़र पाकिस्तान को ये देश 'पश्चिम' तथा दक्षिण एशिया में पश्चिमी हितों का रखवाला मानते हैं।

DEMOCRACY IN BANGLADESH

Bangladesh was a part of Pakistan from 1947 to 1971. It consisted of the partitioned areas of Bengal and **Assam from British India. The** people of this region resented the domination of western Pakistan and Soon after the partition, they began protests against the unfair treatment meted out to the Bengali culture and language. They also demanded fair representation in administration and a fair share in political power. Sheikh Mujibur Rahman led the popular struggle against West Pakistani domination. He demanded autonomy for the eastern region. In the 1970 elections in the then Pakistan, the Awami League led by Sheikh Mujib won all the seats in East Pakistan and secured a maiority in the proposed

बांग्लादेश में लोकतंत्र

1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। अंग्रेजी राज के समय के बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का यह क्षेत्र बना था। इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा the imposition of the Urdu language. को लादने के ख़िला के थे। पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहां के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया। इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में अपने न्यायोचित प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की माँग भी उठायी। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ़ जन-संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर्रहमान ने किया। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की माँग की। शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग को 1970 के चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिली

But the government dominated by the West Pakistani leadership refused to convene the assembly. Sheikh Mujib was arrested. Under the military rule of General Yahya Khan, the Pakistani army tried to suppress the mass movement of the Bengali people. Thousands were killed by the Pakistan army. This led to a large scale migration into India, creating a huge refugee problem for India. The government of India supported the demand of the people of East Pakistan for their independence and helped them financially and militarily. This resulted in a war between India and Pakistan in December 1971 that ended in the surrender of the Pakistani forces in East Pakistan and the formation of Bangladesh as an independent country

अवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया। लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था और सरकार ने इस सभा को आहूत करने से इंकार कर दिया। शेख मुज़ीब को गिर फ्तार कर लिया गया। जेनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथो मारे गए। इस वज़ह से पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन कर गए। भारत के सामने इन शरणार्थियों को संभालने की समस्या आन खड़ी हुई। भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आजादी की माँग का समर्थन किया और उन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता दी। इसके परिणामस्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड गया। युद्ध की समाप्ति पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण तथा एक स्वतंत्र राष्ट 'बांग्लादेश' के निर्माण के साथ हुई।

Bangladesh drafted its constitution declaring faith in secularism, democracy and socialism. However, in 1975 Sheikh Mujib got the constitution amended to shift from the parliamentary to presidential form of government. He also abolished all parties except his own, the Awami League. This led to conflicts and tensions. In a dramatic and tragic development, he was assassinated in a military uprising in August 1975. The new military ruler, Ziaur Rahman, formed his own **Bangladesh National Party and**

बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। बहरहाल. 1975 में शेख मुजीबुर्रहमान ने संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता मिली। शेख मुज़ीब ने अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया। इससे तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। 1975 के अगस्त में सेना ने उनके ख़िलाफ बगावत कर दी और इस नाटकीय तथा त्रासद घटनाक्रम में शेख मुज़ीब सेना के हाथो मारे गए। नये सैनिक-शासक जियाउर्रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनायी और 1979 के चुनाव में विजयी रहे।

He was assassinated and another military takeover followed under the leadership of Lt Gen H. M. Ershad. The people of Bangladesh soon rose in support of the demand for democracy. Students were in the forefront. Ershad was forced to allow political activity on a limited scale. He was later elected as President for five years. Mass public protests made Ershad step down in 1990. Elections were held in 1991. Since then representative democracy based on multi-party elections has been working in Bangladesh.

जियाउर्रहमान की हत्या हुई और लेफ्टिनेंट ज़ेनरल एच एम इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक और सैनिक-शासन ने बागडोर संभाली। लेकिन, बांग्लादेश की जनता जल्दी ही लोकतंत्र के समर्थन में उठ खड़ी हुई। आंदोलन में छात्र आगे-आगे चल रहे थे। बाध्य होकर जेनरल इरशाद ने एक हद तक राजनीतिक गतिविधियों की छूट दी। इसके बाद के समय में जेनरल इरशाद पाँच सालों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। जनता के व्यापक विरोध के आगे झकते हुए लेफ्टिनेंट जेनरल इरशाद को राष्ट्रपति का पद 1990 में छोड़ना पड़ा। 1991 में चुनाव हुए। इसके बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम है।

A mural in Dhaka **University to** remember **Noor Hossain** who was killed by the police during prodemocracy protests against General **Ershad in** 1987. Painted on his back: "Let **Democracy be** Freed". Photo credit: **Shahidul** Alam/ Drik



1987 में जेनरल इरशाद के खिलाफ लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा मारे गए नूर हुसैन की याद में ढाक विश्वविद्यालय में दीवार पर बनी एक चित्रमाला। उसकी पीठ पर अंकित है - गणतंत्र मुक्त पाक। दीवार पर 'जय बांग्ला'. 'जय बंगबंधु', 'विप्लववीर ही सच्चे इंसान हैं' और 'क्रांति ही मुक्ति का इकलौता रास्ता है' जैसे नारे लिखे शाहिदुल आलम, ड्रिक से साभार

MONARCHY AND DEMOCRACY नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र IN NEPAL

Nepal was a Hindu kingdom in the past and then a constitutional monarchy in the modern period for many years. Throughout this period, political parties and the common people of Nepal have wanted a more open and responsive system of government. But the king, with the help of the army, retained full control over the government and restricted the expansion of democracy in Nepal.

नेपाल अतीत में एक हिन्दू-राज्य था फिर आध्निक काल में कई सालों तक यहां संवैधानिक राजतंत्र रहा। संवैधानिक राजतंत्र के दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता ज्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज उठाते रहे। लेकिन राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया और नेपाल में लोकतंत्र की राह अवरुद्ध हो गई।

The king accepted the demand for a new democratic constitution in 1990, in the wake of a strong prodemocracy movement. However, democratic governments had a short and troubled career. During the nineties, the Maoists of Nepal were successful in spreading their influence in many parts of Nepal. They believed in armed insurrection against the monarch and the ruling elite. This led to a violent conflict between the Maoist guerrillas and the armed forces of the king. For some time, there was a triangular conflict among the monarchist forces, the democrats and the Maoists. In 2002, the king abolished the parliament and dismissed the government, thus ending even the limited democracy that existed in

एक मजबूत लोकतंत्र-समर्थक आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की माँग मान ली। नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा और समस्याओं से भरा रहा। 1990 के दशक में नेपाल के माओवादी नेपाल के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हुए। माओवादी, राजा और सत्ताधारी अभिजन के खिलाप म सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे। इस वज़ह से राजा की सेना और माओवादी गुरिल्लों के बीच हिंसक लड़ाई छिड गई। कुछ समय तक राजा की सेना, लोकतंत्र-समर्थकों और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और सरकार को गिरा दिया। इस तरह नेपाल में जो भी थोड़ा-बहुत लोकतंत्र था उसे राजा ने खत्म कर दिया।

In April 2006, there were massive, country wide, prodemocracy protests. The struggling prodemocracy forces achieved their first major victory when the king was forced to restore the **House of Representatives** that had been dissolved in **April 2002. The largely** non-violent movement was led by the Seven Party Alliance (SPA), the Maoists and social activists.

अप्रैल 2006 में यहां देशव्यापी लोकतंत्र- समर्थक प्रदर्शन हुए। संघर्षरत लोकतंत्र-समर्थक शक्तियों ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की जब राजा ज्ञानेन्द्र ने बाध्य होकर संसद को बहाल किया। इसे अप्रैल 2002 में भंग कर दिया गया था। मोटे तौर पर अहिंसक रहे इस प्रतिरोध का नेतृत्व सात दलों के गठबंधन (सेवेन पार्टी अलाएंस), माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया।

The aoist Party joined mainstream politics following the success of the peaceful democratic revolution of 2006;^[69] Nepal became a secular state;^[70] and on 28 May 2008, it was declared status as the world's only Hindu Kingdom. [71] The country's new designation as the Federal Democratic Republic of Nepal was submitted to the United Nations on 4 Agust 2008,^[72] and later confirmed by the constitution. After a decade of instability and internal strife which saw two constituent assembly elections, the new constitution was promulgated on 20 September 2015, making Nepal a fedral democratic republic divided into seven provinces.^{[73][74]}

2006 की शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक क्रांति की सफलता के बाद, ओयोस्ट पार्टी मुख्यधारा की राजनीति में शामिल हो गर्ड: [69] नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया: [joinedo] और २ 2008 मई २००, को इसे दुनिया का एकमात्र हिंदु साम्राज्य का दर्जा दिया गया। ['s?] नेपाल के संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में देश का नया पदनाम ४ अगस्ट २००१ ['इ२] को संयक्त राष्ट्र में प्रस्तुत किया गया और बाद में संविधान द्वारा इसकी पृष्टि की गई। एक दशक की अस्थिरता और आंतरिक कलह के बाद, जिसमें दो घटक विधानसभा चुनाव हुए, 20 सितंबर 2015 को नए संविधान का प्रचार किया गया, जिससे नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन ग्या, जो सात प्रांतों में विभाजित है।

ETHNIC CONFLICT AND DEMOCRACY IN SRI LANKA

We have already seen that Sri Lanka has retained democracy since its independence in 1948. But it faced a serious challenge, not from the military or monarchy but rather from ethnic conflict leading to the demand for secession by one of the regions.

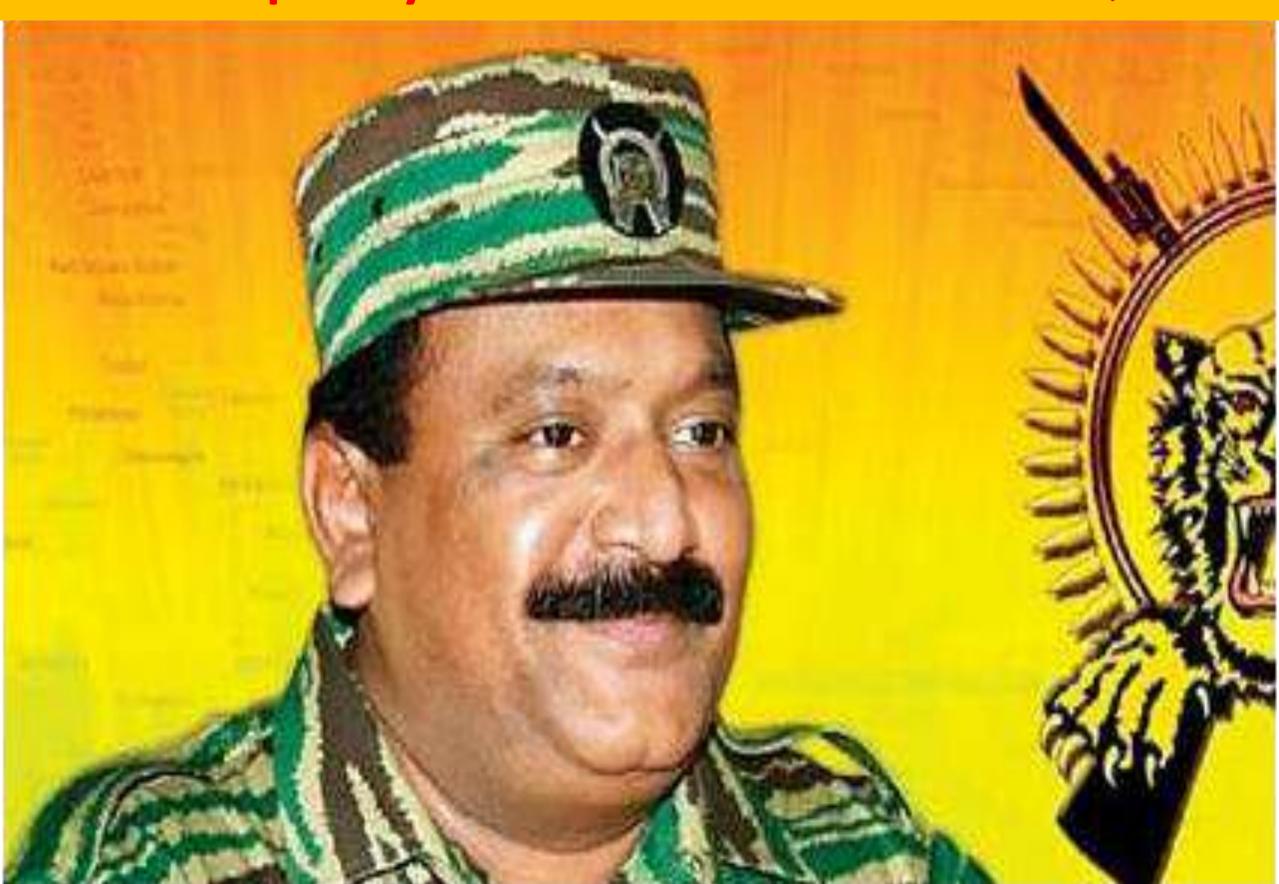
श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र हम देख चुके हैं कि आज़ादी (1948) के बाद से लेकर अब तक श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है। लेकिन. श्रीलंका को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। यह चुनौती न तो सेना की थी और न ही राजतंत्र की। श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पडा जिसकी माँग है कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट बनाया जाय।

After its independence, politics in Sri Lanka (it was then known as **Ceylon) was dominated by forces** that represented the interest of the majority Sinhala community. They were hostile to a large number of Tamils who had migrated from India to Sri Lanka and settled there. This migration continued even after independence. The Sinhala nationalists thought that Sri Lanka should not give 'concessions' to the Tamils because Sri Lanka belongs to the Sinhala people only. The neglect of Tamil concerns led to militant Tamil nationalism. From 1983 onwards, the militant organisation, the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) has been fighting an armed struggle with the army of Sri Lanka and demanding 'Tamil Eelam' or a separate country for the Tamils of Cri Lanka The LTTE controle the

आजादी के बाद से (श्रीलंका को उन दिनों सिलोन कहा जाता था) श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सिंहली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी करे वालों का दबदबा रहा है। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आ बसी एक बड़ी तमिल आबादी के खिलाप हु हैं। तिमलों का बसना श्रीलंका के आज़ाद होने के बाद भी जारी रहा। सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तिमलों के साथ कोई 'रियायत' नहीं बरती जानी चाहिए क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिंहली लोगों का है। तिमलों के प्रति उपेक्षा भरे बरताव से एक उग्र तिमल राष्ट्रवाद की आवाज बुलंद हुई। 1983 के बाद से उग्र तिमल संगठन 'लिबरेशन टाइगर्स ऑव तिमल ईलम' (लिट्टे) श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। इसने 'तिमल ईलम' यानी श्रीलंका के तिमलों के लिए एक अलग देश की माँग की है। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण है।

The Sri Lankan problem involves people of Indian origin, and there is considerable pressure from the Tamil people in India to the effect that the Indian government should protect the interests of the Tamils in Sri Lanka. The government of India has from time to time tried to negotiate with the Sri Lankan government on the Tamil question. But in 1987, the government of India for the first time got directly involved in the Sri Lankan Tamil question. India signed an accord with Sri Lanka and sent troops to stabilise relations between the Sri Lankan government and the Tamils. **Eventually, the Indian Army got into a** fight with the LTTE. The presence of Indian troops was also not liked much by the Sri Lankans. They saw this as an attempt by India to interfere in the internal affairs of Sri Lanka. In 1989, the Indian Peace Keeping Force (IDKE) pulled out of Sri Lapka without

श्रीलंका की समस्या भारतवंशी लोगों से जुड़ी है। भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर भारी दबाव है कि वह श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा करे। भारतीय सरकार ने समय समय पर तिमलों के सवाल पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत की कोशिश की है। लेकिन 1987 में भारतीय सरकार श्रीलंका के तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई। भारत की सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया तथा श्रीलंका सरकार और तिमलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय सेना को भेजा। आखिर में भारतीय सेना लि के साथ संघर्ष में फंस गई। भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने भी कुछ खास पसंद नहीं किया। श्रीलंकाई जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहा है। 1989 में भारत ने अपनी 'शांति सेना' लक्ष्य हासिल किए बिना वापस बुला ली।





The cartoon depicts the dilemma of the Sri Lankan leadership in trying to balance Sinhala hardliners or the Lion and Tamil militants or the Tiger while negotiating peace.

यह कार्टून शांति वार्ताओं में श्रीलंका के नेतृत्व के आगे मौजूद दुविधा को दिखाता है। एक ओर शेर के रूप में सिंहली कट्टरपंथी हैं और दूसरी ओर बाघ के रूप में तिमल उग्रवादी।

In spite of the conflict, Sri Lanka has registered considerable economic growth and recorded high levels of human development. Sri Lanka was one of the first developing countries to successfully control the rate of growth of population, the first country in the region to liberalise the economy, and it has had the highest per capita gross domestic product (GDP) for many years right through the civil war. Despite the ravages of internal conflict, it has maintained a democratic political system.

संघषों की चपेट में होने के बाद भी श्रीलंका ने अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को हासिल किया है। जनसंख्या की वृद्धि-दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम है। दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। गृहयुद्ध से गुजरने के बावजूद कई सालों से इस देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। अंदरूनी संघर्ष के झंझावातों को झलकर भी श्रीलंका ने लोकतांत्रिक राजव्यवस्था कायम रखी है।

INDIA-PAKISTAN CONFLICTS

Let us now move from domestic politics and take a look at some of the areas of conflict in the international relations in this region. The post-Cold War era has not meant the end of conflicts and tensions in this region. We have already noted the conflicts around internal democracy or ethnic differences. But there are also some very crucial conflicts of an international nature. Given the position of India in this region, most of these conflicts involve India.

भारत-पाकिस्तान संघर्ष

आइए, अब हम घरेलू राजनीति के दायरे से बाहर निकलें और इस क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एसे दायरों पर नजर डालें जहां संघर्ष हुए हैं। शीतयुद्ध की समाप्ति का यह अर्थ नहीं कि इस इलाके में भी संघर्ष और तनाव समाप्त हो गए। हम आंतरिक लोकतंत्र या जातीय संघर्ष के मसलों पर हुए टकरावों को देख चुके हैं। लेकिन, कुछ महत्त्वपूर्ण संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के भी हैं। दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति केंद्रीय है और इस वज़ह से इनमें से अधिकांश संघषों का रिश्ता भारत से है।

The most salient and overwhelming of these conflicts is, of course, the one between India and Pakistan. Soon after the partition, the two countries got embroiled in a conflict over the fate of Kashmir. The Pakistani government claimed that Kashmir belonged to it. Wars between India and Pakistan in 1947-48 and 1965 failed to settle the matter. The 1947-48 war resulted in the division of the province into Pakistan-occupied Kashmir and the Indian province of Jammu and Kashmir divided by the Line of Control. In 1971, India won a decisive war against Pakistan but the Kashmir issue remained

इन संघषों में सबसे प्रमुख और सर्वग्रासी संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष है। विभाजन के तुरंत बाद दोनों देश कश्मीर के मसले पर लंड पड़े। पाकिस्तान की सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947-48 तथा 1965 के युद्ध से इस मसले का समाधान नहीं हुआ। 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया जबिक दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू-कश्मीर प्रान्त बना। दोनों के बीच एक नियंत्रण-सीमा रेखा है। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीता लेकिन कश्मीर मसला अनसुलझा ही रहा।

India's conflict with Pakistan is also over strategic issues like the control of the Siachen glacier and over acquisition of arms. The arms race between the two countries assumed a new character with both states acquiring nuclear weapons and missiles to deliver such arms against each other in the 1990s. In 1998, India conducted nuclear explosion in Pokaran. Pakistan responded within a few days by carrying out nuclear tests in the Chagai Hills. Since then India and Pakistan seem to have built a military relationship in which the possibility of a direct and full-scale war has declined.

सामरिक मसलों जैसे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा हथियारों की होड को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी रहती है। 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु हथियार और एसे हथियारों को एक-दूसरे पर दागने की क्षमता वाले मिसाइल हासिल कर लिए। इससे दोनों देशों के बीच हथियारों की होड ने एक नया चरित्र ग्रहण किया है। 1998 में भारत ने पोखरण में और इसके कुछ दिनों के अंदर ही पाकिस्तान ने चगाई पहाडी पर परमाण्-परीक्षण किए। इसके बाद से एसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान एक सैन्य-संबंध में बंध चुके हैं और इनके बीच सीधे और सर्वव्यापी युद्ध छिड्ने की आशंका कम हो गई है।

But both the governments continue to be suspicious of each other. The Indian government has blamed the Pakistan government for using a strategy of low-key violence by helping the Kashmiri militants with arms, training, money and protection to carry out terrorist strikes against India. The Indian government also believes that Pakistan had aided the proKhalistani militants with arms and ammunitions during the period 1985-1995. Its spy agency, Inter Services Intelligence (ISI), is alleged to be involved in various anti-India campaigns in India's northeast, operating secretly through Bangladesh and Nepal. The government of Pakistan, in turn, blames the Indian government and its security agencies for fomenting trouble in the provinces of Sindh

लेकिन, दोनों देशों की सरकारें लगातार एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखती हैं। भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने लुके-छुपे ढंग से हिंसा की रणनीति जारी रखी है। आरोप है कि वह कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देता है तथा भारत पर आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। भारत सरकार का यह भी मानना है कि पाकिस्तान ने 1985-1995 की अवधि में खालिस्तान-समर्थक उग्रवादियों को हथियार तथा गोले-बारुद दिए थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इं टेलीजेंस (आईएसआई) पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत-विरोधी अभियानों में संलग्न होने का आरोप है। इसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियों पर सिंध और बलूचिस्तान में समस्या को भड़काने का आरोप लगाती है।

India and Pakistan also have had problems over the sharing of river waters. Until 1960, they were locked in a fierce argument over the use of the rivers of the Indus basin. Eventually, in 1960, with the help of the World Bank, India and Pakistan signed the Indus Waters Treaty which has survived to this day in spite of various military conflicts in which the two countries have been involved. There are still some minor differences about the interpretation of the Indus Waters Treaty and the use of the river waters. The two countries are not in agreement over the demarcation line in Sir Creek in the Rann of Kutch. The dispute seems minor, but there is an underlying worry that how the dispute is settled may have an impact on the control of sea resources in the area adjoining Sir Creek. India and Pakistan are holding negotiations on all thaca iccuas

भारत और पाकिस्तान के बीच नदी- जल के बँटवारे के सवाल पर भी तनातनी हुई है। 1960 तक दोनों के बीच सिन्धु नदी के इस्तेमाल को लेकर तीखे विवाद हुए। संयोग से, 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने 'सिंधु-जल संधि' पर दस्तख़त किए और यह संधि भारत-पाक के बीच कई सैन्य संघर्षों के बावजूद अब भी कायम है। हालाँकि सिंधु जल-संधि की व्याख्या और नदी-जल के इस्तेमाल को लेकर अभी भी कुछ छोटे-मोटे विवाद हैं। कच्छ के रन में सरक्रिक की सीमारेखा को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद हैं। यह विवाद छोटा जान पड़ता है लेकिन इसके साथ एक चिन्ता ज डी हुई है। इस विवाद का समाधान जिस ढंग से किया जाएगा उसका असर सरक्रिक इलाके से सटे समुद्री-संसाधन के नियंत्रण पर भी पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच इन सभी मामलों के बारे में वार्ताओं के दौर चल रहे हैं।

INDIA AND ITS OTHER NEIGHBOURS

The governments of India and Bangladesh have had differences over several issues including the sharing of the Ganga and Brahmaputra river waters. The Indian government has been unhappy with Bangladesh's denial of illegal immigration to India, its support for anti-Indian Islamic fundamentalist groups, Bangladesh's refusal to allow Indian troops to move through its territory to northeastern India, and its decision not to export natural gas to India or allow Myanmar to do so through Bangladeshi territory. Bangladeshi governments have felt that the Indian government behaves like a regional bully over the sharing of river waters, encouraging rebellion in the Chittagong Hill Tracts, trying to extract its natural gas and being unfair in trade. The two countries could not resolve their haundary disputa for a lang while

भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश

बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद हैं। भारतीय सरकारों के बांग्लादेश से नाखुश होने के कारणों में भारत में अवैध आप्रवास पर ढाक के खंडन, भारत-विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों को समर्थन, भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से बांग्लादेश के इंकार, ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने के फैसले तथा म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देने जैसे मसले शामिल हैं। बांग्लादेश की सरकार का मानना है कि भारतीय सरकार नदी-जल में हिस्सेदारी के सवाल पर इलाके के दादा की तरह बरताव करती है। इसके अलावा भारत की सरकार पर चटगाँव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देने; बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करने और व्यापार में बेईमानी बरतने के भी आरोप है

Despite their differences, India and Bangladesh do cooperate on many issues. Economic relations have improved considerably in the last 20 years. Bangladesh is a part of **India's Look East (Act East** since 2014) policy that wants to link up with Southeast Asia via Myanmar. On disaster management and environmental issues, the two states have cooperated regularly. In 2015, they exchanged certain enclaves. Efforts are on to broaden the areas of cooperation further by identifying common threats and being more sensitive to

विभेदों के बावजूद भारत और बांग्लादेश कई मसलों पर सहयोग करते हैं। पिछले बीस वषों के दौरान दोनों के बीच आर्थिक संबंध ज्यादा बेहतर हुए हैं। बांग्लादेश भारत के 'लुक ईस्ट' और 2014 से 'एक्ट ईस्ट' नीति का हिस्सा है। इस नीति के अन्तर्गत म्यांमार के ज़रिए दक्षिण-पूर्व एशिया से संपर्क साध ने की बात है। आपदा-प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर भी दोनों देशों ने निरंतर सहयोग किया है। 2015 में दोनों ने कुछ परिक्षेत्रों (एन्केलेव) का आदान-प्रदान किया। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि साझे खतरों को पहचान कर तथा एक दूसरे की ज़रूरतों के प्रति ज्यादा संवेदनशीलता बरतकर सहयोग के दायरे को बढाया जाए।

Nepal and India enjoy a very special relationship that has very few parallels in the world. A treaty between the two countries allows the citizens of the two countries to travel to and work in the other country without visas and passports. Despite this special relationship, the governments of the two countries have had traderelated disputes in the past. The Indian government has often expressed displeasure at the warm relationship between Nepal and China and at the Nepal government's inaction against antilndian elements. Indian security agencies see the Maoist movement in Nepal as a growing security threat, given the rise of Naxalite groups in various Indian states from Rihar in the north to

भारत और नेपाल के बीच मध्र संबंध हैं और दोनों देशों के बीच एक संधि हुई है। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक-दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट (पारपत्र) और वीज़ा के आ-जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। ख़ास संबंधों के बावजूद दोनों देश के बीच अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव पैदा हुए हैं। नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता जतायी है। नेपाल सरकार भारत-विरोधी तत्त्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती। इससे भी भारत नाखुश है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती हैं क्योंकि भारत में बिहार से लेकर आन्ध्र प्रदेश तक विभिन्न प्रांतों में नक्सलवादी समूहों का उभार हुआ है

Many leaders and citizens in Nepal think that the Indian government interferes in its internal affairs, has designs on its river waters and hydroelectricity, and prevents Nepal, a landlocked country, from getting easier access to the sea through Indian territory. Nevertheless, **Indo-Nepal relations are fairly** stable and peaceful. Despite differences, trade, scientific cooperation, common natural resources, electricity generation and interlocking water management grids hold the two countries together. There is a hope that the consolidation of democracy in Nepal will lead to improvements in the ties

नेपाल में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है और उसके नदी जल तथा पनिबजली पर आंख गडाए हुए है। चारों तरफ से जमीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत उसको अपने भूक्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुँचने से रोकता है। बहरहाल भारत-नेपाल के संबंध एकदम मज़बूत और शांतिपूर्ण है। विभेदों के बावजूद दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाध न, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन ग्रिड के मसले पर एक साथ हैं। नेपाल में लोकतन्त्र की बहाली से दोनों देशों के बीच संबंधों के और मज़बूत होने की उम्मीद बंधी है।

The difficulties in the relationship between the governments of India and Sri Lanka are mostly over ethnic conflict in the island nation. Indian leaders and citizens find it impossible to remain neutral when Tamils are politically unhappy and are being killed. After the military intervention in 1987, the Indian government now prefers a policy of disengagement vis-à-vis Sri Lanka's internal troubles. India signed a free trade agreement with Sri Lanka, which strengthened relations between two countries. India's help in post-tsunami reconstruction in Sri Lanka has also brought the

श्रीलंका और भारत की सरकारों के संबंधों में तनाव इस द्वीप में जारी जातीय संघर्ष को लेकर है। जब तिमल आबादी राजनीतिक रूप से नाखुश हो और उसे मारा जा रहा हो तो एसे में भारतीय नेताओं और जनता का तटस्थ बने रहना असंभव लगता है। 1987 के सैन्य हस्तक्षेप के बाद से भारतीय सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में असलंग्नता की नीति पर अमल कर रही है। भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत किए हैं। इससे दोनों देशों के संबंध मज़बूत हुए हैं। श्रीलंका में 'सुनामी' से हुई तबाही के बाद के पुनर्निर्माण कायों में भारतीय मदद से भी दोनों देश एक दूसरे के करीब आए हैं।

India enjoys a very special relationship with Bhutan too and does not have any major conflict with the Bhutanese government. The efforts made by the Bhutanese monarch to weed out the guerrillas and militants from northeastern India that operate in his country have been helpful to India. India is involved in big hydroelectric projects in Bhutan and remains the Himalayan kingdom's biggest source of development aid. India's ties with the Maldives remain warm and cordial. In November 1988, when some Tamil mercenaries from Sri Lanka attacked the Maldives, the Indian air force and navy reacted quickly to the Maldives' request to help stop the invasion. India has also contributed towards the island's economic development,

भारत के भूटान के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं और भूटानी सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुरिल्लों को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड भगाया। भूटान के इस कदम से भारत को बड़ी मदद मिली है। भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजनाओं में हाथ बँटा रहा है। इस हिमालयी देश के विकास कायों के लिए सबसे ज्यादा अनुदान भारत से हासिल होता है। मालदीव के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण तथा गर्मजोशी से भरे हैं। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तिमल सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया। मालदीव ने जब आक्रमण रोकने के लिए भारत से मदद माँगी तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी मदद की है।

You may have noticed that India has various problems with its smaller neighbours in the region. Given its size and power, they are bound to be suspicious of India's intentions. The Indian government, on the other hand, often feels exploited by its neighbours. It does not like the political instability in these countries, fearing it can help outside powers to gain influence in the region. The smaller countries fear that India wants to be a regionallydominant power.

आपने ध्यान दिया होगा कि दक्षिण एशिया के छोटे-छोटे पड़ोसियों के साथ भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत का आकार बड़ा है और वह शक्तिशाली है। इसकी वज़ह से अपेक्षाकृत छोटे देशों का भारत के इरादों को लेकर शक करना लाजिमी है। दूसरी तरफ, भारत सरकार को अक्सर महसूस होता है कि उसके पड़ोसी देश उसका बेज़ा फायदा उठा रहे हैं। भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। उसे भय लगता है कि एसी स्थिति में बाहरी ताकतों को इस क्षेत्र में प्रभाव जमाने में मदद मिलेगी। छोटे देशों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है।

Not all conflicts in South Asia are between India and its neighbours. Nepal and Bhutan, as well as Bangladesh and Myanmar, have had disagreements in the past over the migration of ethnic **Nepalese into Bhutan and the** Rohingyas into Myanmar, respectively. Bangladesh and Nepal have had some differences over the future of the Himalayan river waters. The major conflicts and differences, though, are between India and the others, partly because of the geography of the region, in which India is located centrally and is therefore the only country that borders the

दक्षिण एशिया के सारे झगड़े सिर्फ भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच ही नहीं है। नेपाल-भूटान तथा बांग्लादेश -म्यांमार के बीच जातीय मूल के नेपालियों के भूटान आप्रवास तथा रोहिंग्या लोगों के म्यांमार में आप्रवास के मसले पर मतभेद रहे हैं। बांग्लादेश और नेपाल के बीच हिमालयी निदयों के जल की हिस्सेदारी को लेकर खटपट है। यह बात सही है कि इस इलाके के सभी बड़े झगडे भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच हैं। इसका एक कारण दक्षिण एशिया का भूगोल भी है जहां भारत बीच में स्थित है और बाकी देश भारत की सीमा के इर्द-गिर्द पड़ते हैं।

PEACE AND COOPERATION

Do the states of South Asia cooperate with each other? Or do they only keep fighting with each other? In spite of the many conflicts, the states of South Asia recognise the importance of cooperation and friendly relationship, among themselves. The South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) is a major regional initiative by the **South Asian states to evolve** cooperation through multilateral means. It began in 1985. Unfortunately, due to persisting political differences, SAARC has not had much success. SAARC members signed the South Asian Free Trade (SAFTA) agreement which promised the formation of a free trade zone for the whole of

शांति और सहयोग

क्या दक्षिण एशिया के देश एक-दूसरे का सहयोग करते हैं या ये देश एक-दूसरे से सिप र् लड़ते रहते हैं? अनेक संघषों के बावजूद दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ते तथा सहयोग के महत्त्व को पहचानते हैं। शांति के प्रयास द्विपक्षीय भी हुए हैं और क्षेत्रीय स्तर पर भी। दक्षेस (साउथ एशियन एसोशियन फॉर रिजनल कोऑपरेशन (।।त्क) दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई। दुर्भाग्य से विभेदों की मौजूदगी के कारण दक्षेस को ज्यादा सफलता नहीं मिली है। दक्षेस के सदस्य देशों ने सन् 2002 में 'दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार-क्षेत्र समझौते' (SAFTA) पर दस्तख़त किये। इसमें पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वायदा है।

A new chapter of peace and cooperation might evolve in South Asia if all the countries in the region allow free trade across the borders. This is the spirit behind the idea of **SAFTA.** The Agreement was signed in 2004 and came into effect on 1 January 2006. SAFTA aims at lowering trade tariffs. But some of our neighbours fear that SAFTA is a way for India to 'invade' their markets and to influence their societies and politics through commercial ventures and a commercial presence in their countries. India thinks that there are real economic benefits for all from SAFTA and that a region that trades more freely will be able to cooperate better on political issues. Some in India think that SAFTA is not worth the trouble since India alroady hae hilatoral agroomonte

यदि दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमारेखा के आर-पार मुक्त-व्यापार पर सहमत हो जाएँ तो इस क्षेत्र में शांति और सहयोग के एक नए अध्याय की श्रुआत हो सकती है। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते (ै।थ्ना) के पीछे यही भावना काम कर रही है। इस समझौते पर 2004 में हस्ताक्षर हुए और यह समझौता 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया। इस समझौते का लक्ष्य है कि इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को कम कर दिया जाए। कुछ छोटे देश मानते हैं कि 'साफ्टा' की ओट लेकर भारत उनके बाज़ार में सेंध मारना चाहता है। और व्यावसायिक उद्यम तथा व्यावसायिक मौजूदगी के जरिये उनके समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है। भारत सोचता है कि 'साफ्टा' से इस क्षेत्र के हर देश को फायदा होगा और क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ्न से राजनीतिक मसलों पर सहयोग ज्यादा बेहतर होगा। भारत में कुछ लोगों का मानना है कि 'साफ्टा' के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि भारत भूटान, नेपाल और श्रीलंका से पहले ही द्विपक्षीय व्यापार समझौता कर चुका है।

No region exists in a vacuum. It is influenced by outside powers and events no matter how much it may try to insulate itself from nonregional powers. China and the **United States remain key** players in South Asian politics. Sino-Indian relations have improved significantly in the last ten years, but China's strategic partnership with Pakistan remains a major irritant. The demands of development and globalisation have brought the two Asian giants closer, and their economic ties have multiplied rapidly since 1991.

कोई भी क्षेत्र हवा में नहीं होता। चाहे कोई क्षेत्र अपने को गैर इलाकाई ताकतों से अलग रखने की जितनी भी कोशिश करे उस पर बाहरी ताकतों और घटनाओं का असर पड़ता ही है। चीन और संयुक्त राज्य अमरीका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। पिछले दस वषों में भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए हैं। चीन की रणनीतिक साझदारी पाकिस्तान के साथ है और यह भारत-चीन संबंधों में एक बड़ी कठिनाई है। विकास की जुरूरत और वैश्वीकरण के कारण एशिया महादेश के ये दो बड़े देश ज्यादा नजदीक आये हैं। सन् 1991 के बाद से इनके आर्थिक संबंध ज्यादा मज़बूत हुए हैं।

American involvement in South Asia has rapidly increased after the Cold War. The US has had good relations with both India and Pakistan since the end of the Cold War and increasingly works as a moderator in India-Pakistan relations. Economic reforms and liberal economic policies in both countries have greatly increased the depth of American participation in the region. The large South Asian diasporas in the US and the huge size of the population and markets of the region also give America an added stake in the future of regional

शीतयुद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमरीकी प्रभाव तेजी से बढ़ा है। अमरीका ने शीतयुद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध बेहतर किए हैं। वह भारत-पाक के बीच लगातार मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। दोनों देशों में आर्थिक सुधार हुए हैं और उदार नीतियां अपनाई गई हैं। इससे दक्षिण एशिया में अमरीकी भागीदारी ज्यादा गहरी हुई है। अमरीका में दक्षिणशयाई मूल के लोगों की संख्या अच्छी-खासी है। फिर, इस क्षेत्र की जनसंख्या और बाजार का आकार भी भारी भरकम है। इस कारण इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के भविष्य से अमरीका के हित भी बंधे हुए हैं।

However, whether South Asia will continue to be known as a conflict prone zone or will evolve into a regional bloc with some common cultural features and trade interests will depend more on the people and the governments of the

region than any other

outside power.

What does this cartoon tell you about the role of India and Pakistan in the process of regional cooperation in South Asia?

बहरहाल, दक्षिण एशिया को संघषों की आशंका वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता रहेगा अथवा यह एक एसे क्षत्रीय गुट के रूप में उभरेगा जिसके सांस्कृतिक गुण-धर्म तथा व्यापारिक हित एक हैं – यह बात किसी बाहरी शक्ति से ज्यादा यहां के लोगों और सरकारों पर निर्भर है।

> यह कार्टून क्षेत्रीय सहयोग की प्रगति में भारत और पाकिस्तान की भूमिका के बारे में क्या बताता है?